International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 11 Issue 4, July-August, 2023, Impact Factor: 7.326

झारखण्ड में समग्र–शिक्षा के बुनियादी सुविधाओं के कार्यान्वयन की स्थितिः एक सर्वेक्षण

नीता रजक[1], डॉ0 विनय कुमार[2]

[1]शोधार्थी, राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड
[2]सह सहायक प्राध्यापक,राधा गोविंद विश्वविद्यालय, रामगढ़, झारखंड

प्रस्तावना

शिक्षा वह प्रकाश है जिसके द्वारा बालक की समस्त शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, इससे वह समाज का एक उतरदायी घटक एवं राष्ट्र का प्रखर चरित्र सम्पन्न नागरिक बनकर समाज की सर्वांगीण उन्नति में योगदान करता है। शिक्षा और जीवन अन्योन्याश्रित है। शिक्षा के द्वारा ही हमारी कीर्ति का प्रकाश चारों और फैलता है तथा शिक्षा ही हमारी समस्याओं को सुलझाती है एवं हमारे जीवन को सुसंस्कृत बनाती है। इस देश में रहे या विदेश में प्रत्येक स्थान पर हमारी सहायता करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पाकर कमल का फुल खिल जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के प्रकाश को पाकर प्रत्येक व्यक्ति कमल के फूल की भांति खिल उठता है तथा अशिक्षित रहने पर दरिद्रता, शोक एवं कष्ट के अधिकार में डुबा रहता है।

शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के द्वारा राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बाँटने की आवश्यकता महसूस की गई। जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भार भी स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखना एवं देश की शैक्षिक जरूरतों का आकलन एवं रखरखाव शामिल है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया, उनमें शिक्षा भी शामिल थी।

समग्र शिक्षा योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा को स्कूल–पूर्व प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों में बाँटा है ताकि इसकी निरंतरता लगातार बनी रह सके। योजना का उद्देश्य अंग्रेजी के और टेक्नोलॉजी का एकीकरण करके सभी स्तरों पर गुणवत्ता में सुधार लाना है। यह योजना विभिन्न स्तरों की शिक्षा को बाँटे बिना स्कूली शिक्षा को समग्र दृष्टि से देखती है। यह योजना ग्रेड अनुसार, विषय अनुसार शिक्षा प्राप्ति के परिणामों पर आधारित है। योजना में सभी हितधारकों– माता–पिता/अभिभावक, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, समुदाय तथा राज्यकर्मी आदि की सक्रिय भागीदारी होती है ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा के लिए समेकित योजना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018–19 में 'समग्र शिक्षा' का शुभारंभ किया। विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में यह एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है, जिसका विस्तार विद्यालय पूर्व से लेकर बारहवीं कक्षा कक्ष है और इसका उद्देश्य है कि विद्यालय शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान विद्यालयी शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जो प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक राज्यों को सहायता प्रदान करती है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (R.M.S.A) और शिक्षक शिक्षा (T.E) की तीन

पूर्ववर्ती योजनाएँ समाहित है। परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालयी परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों के उत्साहवर्धन जैसे बदलावों को चिह्नित करती है। इस योजना में 'विद्यालय' की परिकल्पना विद्यालय–पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गयी है। योजना की दूर दृष्टि में शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य $(S.D.G)$ के अुनसार विद्यालय–पूर्व से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। सतत विकास लक्ष्य 4.1 में कहा गया है कि "सुनिश्चित करें कि 2030 तक सभी लड़के और लड़कियाँ, संगत एवं प्रभावी अधिगम प्रतिफलों की और ले जाने वाली निःशुल्क, न्यायसंगत एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को पूरा करें"।

शोध का उद्देश्य :

- हजारीबाग जिले में समग्र शिक्षा अभियान के तहतमाध्यमिक सरकारी विद्यालयों में बुनियादी ढाँचा का विस्तृत अध्ययन करना।
- सरकारी योजनाओं के तहत माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में जनजातीय छात्राओं को मिलने वाली सुविधओं का अध्ययन करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध की प्रकृति को देखते हुए शोधार्थी द्वारा वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया गया है। वर्णनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान का प्रयोग मुख्य रूप से सामाजिक विज्ञानों में वर्तमान की किसी स्थिति, घटना या वैचारिक चिन्तन आदि से सम्बन्धित समस्या के अध्ययन के लिए किया जाता है।प्रस्तुत शोध में जनसंख्या के रूप में हजारीबाग जिला के प्रखंडों को लिया गया है। हजारीबाग जिला झारखण्ड राज्य में स्थित है। जिले में कुल 15 प्रखंड है। जिनमें पांच प्रखण्डों को मैंने अपने शोध के लिये चुना है–1. बरही प्रखण्ड 2. बरकागाँव प्रखण्ड 3. सदर प्रखण्ड 4. चौपारण प्रखण्ड 5. विष्णुगढ़ प्रखण्ड। आंकड़ों के एक त्रण और संकलन के आरंभ से ही उनके सारणीयन, संगठन, क्रमबद्धता और संक्रियात्मक विश्लेषण तक जबतक कि निष्कर्ष प्राप्त न हो जाए परिशुद्ध सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया जाता है।शोधार्थी ने न्यादर्श संग्रह के लिए चुने गए विद्यालय में एक–एक करके स्वयं जाकर वहाँ के छात्र–छात्राओं को सूचि" को वितरित कर और उनसे सूचि के प्रथम पृष्ठ पर अंकित निर्देश पढ़कर सूचि को हल करने का अनुरोध किया।ये छात्र विभिन्न स्कूलों एवम् अलग अलग पारिवारिक पृष्टभुमियों से आती है। वर्तमान अध्ययन के लिये छात्रों की कुल संख्या 400 है।

तथ्यों का संग्रहण एवं विश्लेषण :

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत अनुसूची के माध्यम से अध्ययन में सम्मिलित प्रत्येक विद्यार्थियों से जो सूचनाएं प्राप्त की गई है, उन्हें उनकी प्रकृति में निहित समानता एवं शोध उद्देश्य हेतु उसकी उपादयेता को ध्यान में रखते हुए उनका वर्गीकरण किया गया है। तथ्यों को स्वतंत्र तथा आश्रित चरों में रखकर उनके अन्तसम्बंधों को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।

वर्तमान अध्ययन में प्रासंगिक साक्ष्य या डेटा प्राप्त करने के लिए शोधकर्ता ने उतरदाताओं अर्थात हेड मास्टर, शिक्षक, तथा छात्रों प्रत्येक से व्यक्तिगत मुलाकात करके आँकडों का संग्रहण किया है। जानकारी एकत्र करने के लिए शोधकर्ता ने पाँच प्रखंडों का चयन किया। उन प्रखंडों में से 25 माध्यमिक विद्यालयों का चयन किया गया। चयन के तहत मल्टी सैंपल तकनीक का प्रयोग किया गया। शोधकर्ता ने प्रश्नावली सह चेकलिस्ट की सहायता से सभी प्रासंगिक स्त्रोतो से डेटा एकत्रित सर्वेक्षण विधि के माध्यम से किया।

तालिका– 1 समग्र शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली बुनियादीसुविधाओं का अध्ययन

क्रम सं0		प्रखण्डों द्वारा प्राप्त उतर (प्रतिशत में)					
	सुविधाएँ	सदर	बडकागांव	चौपारण	विष्णुगढ	बरही	कुल
1	पेयजल सुविधा वाले स्कूलो का प्रतिशत	92.3	81.5	85.9	75.7	88.5	84.78
2	वालिका शौचालय वाले विद्यालय का प्रतिशत	97.7	95.8	92.3	95.9	89.8	94.3
3	घर से 5 किलों मि की दूरी के अंदर के विद्यालय	95.2	86.6	33.2	86.1	76.5	75.52
4	कम्प्यूटर संबंधी सुविधाएँ (**ICT Lab**)	80	76	55	34	45	58
5	पुस्तकालय संबंधी सुविधाएँ	38	23	14	11	26	22.4
6	खेलकुद की सामग्री	61	55	34	12	33	39
7	बस–सेवा	00	00	00	00	00	00
8	कक्षा कक्ष, प्रचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष, आदि	96	95	83	90	82	89.2
9	प्रयोगशाला कक्ष	50.6	45	31.2	00	55	36.36

ब्याख्या–तालिका के अवलोकन से यह तथ्य सामने आता है कि सदरप्रखंड की स्थिती दूसरे प्रखंडों के मुकाबले अच्छी है। बालिका शौचालय वाले विद्यालय का प्रतिशत जहाँ 97.7 के साथ सबसे बेहतर आँकडों में शामिल है वहीं कक्षा कक्ष, प्रचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष आदि,पेयजल सुविधा, घर से 5 किलो. मी. की दूरी के अंदर के विद्यालयकी स्थिती भी 90% के उपर की है।पुस्तकालय संबंधी सुविधाएँ वाले भाग में सामान्य से नीचे की स्थिती (38%) पाई गई वहीं कम्प्यूटर संबंधी सुविधाएँ (ICT Lab) सामान्य (80%) पाई गई। 'खेलो भारत' की स्थिती का जहाँ तक सवाल है वह बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया और खेलकुद की सामग्री का प्रतिशत 61 आया जो खेलकुद की स्थिती अच्छी नहीं है बताता है। बस सेवा नगन्य रहा।बडकागांवप्रखंड केवल कक्षा कक्ष, प्रचार्य कक्ष, कर्मचारी कक्ष आदि तथा बालिका शौचालय वाले विद्यालय का प्रतिशत में 90%के उपर आंकडा प्रस्तुत किया। पेयजल सुविधा वाले स्कूलो का प्रतिशत, घर से 5 किलों मि की दूरी के अंदर के विद्यालय में बडकागांवप्रखंडकी स्थिती भी 80% के उपर की है।पुस्तकालय संबंधी सुविधाएँ वाले भाग में सामान्य से नीचे की स्थिती (23%) पाई गई वहीं कम्प्यूटर संबंधी सुविधाएँ (ICT Lab) सामान्य (76%) पाई गई।चौपारण, विष्णुगढ तथा बरही की स्थिती बडकागांवप्रखंडकी स्थिती जैसी ही पाई गई।

उपरोक्त सारणी शोध प्रश्न 1 के अंतर्गत आते हैं– गुणवतापूर्ण शिक्षा में बुनियादी ढाँचा किस प्रकार योगदान कर रहा है ?

क. बुनियादी सुविधओं की स्थितीः अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के पास (80–96%) हेडमास्टर, कमरे, कार्यालय कक्ष, पुस्तकालय (10–40%), स्टाफ, कॉमनरूम, पेयजल सुविधा, शौचालय(70–95%), आदि हैं पर उनकी स्थिती प्रबंधन के अधीन और खराब है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के पास वाचनालय, खेल का मैदान, छात्रावास, कम्प्यूटर नहीं है साथ–ही साथ शिक्षकों की भी भारी कमी पाई गई। महिला शिक्षकों के लिए अलग शौचालय, सांस्कृतिक कक्ष, लडकियों के लिए छात्रवास आदि में भी भारी कमी पाई गई।

ख. माध्यमिक विद्यालयों की स्थिती : पाठयचर्या घटक एवं सुविधाएँअधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में भाषा, सामाजिक विज्ञान एवं ई–पाठशाला की पहुँच नहीं है।अधिकांश विद्यालयों मेंविज्ञानप्रयोगशाला (44%) नहीं है।अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों के पास पुस्तकालय संबंधी सुविधाएँ (22.4%)भी नहीं है।

ग.माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षण स्टाफ की स्थिती :अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में हेडमास्टर तथा PCM के शिक्षक (67%) नहीं पाए गए। अधिकांश माध्यमिक विद्यालय प्रभारी प्रधानाध्यापक तथा पारा शिक्षकों के अधीन है। पी0टी0 शिक्षक तथा अन्य शिक्षकों की भी कमी साफ दिखाई पडी।अधिकांश शिक्षक नियमित (87%)स्तर के मिले।अधिकांश माध्यमिक विद्यालयों में गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए उचित स्वीकृत पद नहीं है।स्वीकृत पदों पर रीक्तियाँ (78%)पाई गई।

निष्कर्ष :

विद्यालय वह चारदिवारी है जहाँ बच्चों के भविष्य को गढा जाता है जिसमें कार्यरत शिक्षक कुम्हार की भाँति छात्रों को आकार प्रदान कर अर्थपूर्ण पात्र में परिवर्तित करता है। सुविधाओँ को अगर देखा जाए तो वह होने के बावजुद अच्छी स्थिती में नहीं पाई गई अर्थात उसमें मरम्मत की जरूरत है।विद्यालयों की ब्यवस्था इस प्रकार है जो विद्यार्थियों को एक सरकारी लाभ उठाने वाले लाभार्थी के रूप में विकसित कर रही है गुणवतापूर्ण शिक्षा तो एक कोरी कल्पना सी बन कर रह गई है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1]. Azhim Premji Foundation. (2001). Some issues in school education: position papers from Azim Premji foundation. Retrieved 12/02/2020 from https://www.yumpu.com/en/document/read/31673266/issues-in-elementaryeducation-azim-premji-foundation

[2]. Banerjee, A., & Bhardwajan, A.(2022).Empowering girls for a better tomorrow. Employment News. Retrieved 15/09/2020, from https://indianewjobs.com/employment-news-pdffree-download/.
[3]. Baruah, R. (2013). Education of the deprived social group: with special reference to the girl's education of Tinsukia district through KGBV (Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya) with field study. IOSR Journal of Research & Method in Education, 3 (4), 1-6.
[4]. Behera, A. K. (2015). Primary education among tribal people of Mayurbhanj district of Odisha : an evaluative study. International Journal of Humanities and Social Science Invention, 4(2), 43–54.
[5]. Behera, D., & Krishnaiah, R. (2021). Quality issues in school education: Perspectives of National Education Policy 2020 towards achieving SDGs. Akshar Wangmay,1, 20-22.
[6]. Behera, J., and Samal, R.M. (2015). Category (tribe and non-tribe) as a factor in educational aspiration of secondary school students: An investigation. IOSR Journal of Research & Method in Education, 5(4), 01-11.